भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3910

22 दिसम्बर, 2015 को उत्तरार्थ

विषय : मिट्टी की उर्वरता

3910. श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:
श्रीमती मीनाक्षी लेखी:
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री विघुत वरण महतो:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री प्रेम दास राई:
श्री सी.आर.चौधरी:
श्री फिरोज वरूण गांधी:
श्री आलोक संजर:
श्री सिराजुद्धीन अजमल:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री एंटो एन्टोनी:
श्री वी. पन्नीरसेलवम:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में मिट्टी की उर्वरता का मूल्यांकन करने और कृषि मिट्टी का पूरा उपयोग करने के लिए गांवों में आवधिक कैम्प लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस उद्देश्य के लिए विकसित की गयी नयी मिट्टी जांच प्रौद्योगिकी की संख्या और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किसानों का मिट्टी जांच प्रयोगशाला संबंधी अनुपात सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में कृषक मेला और सेमिनारों को आयोजन करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को तेजी देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त योजना को सामान्य किसानों के लिए पहुंच योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों के बारे में किसानों को शिक्षित करने और कृषि को इनके कुप्रभावों से बचाने के लिए कोई अभियान/कार्यक्रम शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या सफलता मिली है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)

(क) और (ख): सभी 14 करोड़ कृषि जोतकों में उर्वरता मूल्यांकन करने एवं 3 वर्ष के अंतराल में नियमित रूप से किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने हेतु 2014-15 से 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (एसएचसी)योजना की शुरूआत की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य एवं इसकी उर्वरता में सुधार करने के लिए लागू किए जाने वाले पोषकों की उपयुक्त खुराक पर सिफारिशों के साथ-साथ किसानों को अपनी मृदा की पोषक स्थितियों पर सूचना प्रदान करता है।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचसी) योजना के तहत, 2014-15 एवं 2015-15 के दौरान 103 नए स्थैलिक एव 77 नई चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की संस्वीकृति की गई है।

मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या एवं फार्म जोतकों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबं**ध पर दिया गया है।

(ग) और (घ): 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में मुद्रण विज्ञापनों, वीडियो स्पॉट एवं रेडियों जिंगल के माध्यम से पूरे देश में स्वास्थ्य कार्ड योजना का आयोजन किया गया। राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर 5 दिसम्बर, 2015 को 'विश्व मृदा दिवस' मनाया गया। पूरे देश में कई केन्द्रीय मंत्री एवं सांसदों ने कार्यक्रम में भाग लिया है। सभी राज्य सरकारों ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का विवरण किया एवं इस अवसर पर कार्यशालाओं, सेमिनारों, रैलियों का आयोजन किया। राज्यों को जागरूक एवं सक्रिय बनाने के लिए लखनऊ (ऊ.प्र.), बैंगलौर (कर्नाटक), दिसपुर (असम), पटना (बिहार) में क्षेत्रीय कार्याशालाओं का आयोजन किया गया है तथा रायपुर (छत्तीसगढ़) में एक और कार्यशाला को आयोजन किया जाना है। सूचना शिक्षण एवं संचार (आईईसी) प्रचार के लिए 73 करोड़ रू की धनराशि निर्धारित की गई है। अभियान को इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में कवर कराए जाने की योजना है।

(ड़): रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशियों को उपयोग पर किसानों को शिक्षित करने एवं ऐसे आदानों के प्रतिकूल प्रभाव से कृषि का संरक्षण करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i सरकार बेहतर मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पौध पौषक प्रबंधन के अजैविक एवं जैविक का सम्मिलित उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित एवं समेकित पोषक प्रबंधन की संस्तूति कर रहा है।

ii राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) की घटक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) के तहत, 20 या उससे अधिक प्रतिभागियों के लिए प्रति प्रशीक्षण 10,000 रू की दर से उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर फिल्ड प्रदर्शन सहित किसानों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रति प्रदर्शन 20,000 रू की दर से फ्रांट लाईन फिल्ड प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाता है। अब तक योजना के तहत 1568 किसान प्रशिक्षण, 1259 प्रदर्शन एवं 977 फ्रांट लाईन फिल्ड प्रदर्शन की स्वीकृति दिया गया है।

iii इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भी इस पहलू पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और करती है, फ्रांट लाईन प्रदर्शन का आयोजन करता है।

iv 'भारत में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना' के तहत समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रम में पौध संरक्षण रणनीति के मूलभूत सिद्धांत एवं मुख्य फलक के रूप में समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) को अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित किया जाता है। आईपीएम कार्यक्रम की सीमा के तहत, भारत सरकार ने 31 केन्द्रीय आईपीएम केन्द्रों की स्थापना की है, जो विभिन्न फसल कीटों एवं खरपतवार के विरूद्ध जैव कीटनाशियों का उपयोग एवं अंतिम उपाय के रूप में रासायनिक कीटनाशियों का विवेक पूर्ण उपयोग सहित यांत्रिक, कृषि एवं जैविक नियंत्रण उपायों के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए किसान फिल्ड विद्यालय (एफएफएस) आयोजित करते हैं।

v कीटनाशी अधिनियम 1968 और इसके तहत निर्धारित नियम यह अधिदेश देता है कि केवल विस्तृत संरक्षण मूल्यांकन के बाद ही भारत में कृषि उपयोग के लिए कीटनाशियों का पंजीकरण किया जाता है। एक बार पंजीकरण के पश्चात एक कीटनाशी किसानों तथा विस्तारकर्मियों आदि के लाभ के लिए कीटनाशियों के संरक्षित उपयोग पर महत्वपूर्ण सूचना सहित अनुमोदित लेबल तथा लीफलेट प्रदर्शित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। लेबल तथा लीफलेटों पर अनुदेशों के अनुसरण में कीटनाशियों के अनुप्रयोग से मानव स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है।

अनुबंध

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा भू-जोतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	एसटीएल की संख्या	भू-जोतों की संख्या
	दक्षिणी जोन		
1	आंध्र प्रदेश	88	131.75
2	कर्नाटक	64	78.32
3	केरल	26	68.31
4	तमिलनाडु	48	81.18
5	पुडुचेरी	2	0.33
6	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0.12
	पूरी तरह से	**228**	**360.01**
	पश्चिमी जोन		
7	गुजरात	139	48.86
8	मध्य प्रदेश	63	88.72
9	महाराष्ट्र	158	136.99
10	राजस्थान	59	68.88
11	दादर और नागर हवेली	0	0.15
12	छत्तीसगढ़	13	37.46
13	गोवा	2	0.78
	कुल	**434**	**381.84**
	उत्तरी जोन		
14	हरियाणा	40	16.17
15	पंजाब	71	10.53
16	उत्तराखंड	16	9.13
17	उत्तर प्रदेश	281	233.25
18	हिमाचल प्रदेश	15	9.61
19	जम्मू और कश्मीर	13	14.49
20	दिल्ली	1	0.2
	कुल	**437**	**293.38**
	पूर्वी जोन		
21	बिहार	39	161.91
22	झारखंड	8	27.09
23	ओडिशा	24	46.67
24	पश्चिम बंगाल	20	71.23
	कुल	**91**	**306.9**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र		
25	असम	11	27.2
26	त्रिपुरा	6	5.78
27	मणिपुर	8	1.51
28	मेघालय	6	2.1
29	नागालैंड	3	1.78
30	अरुणाचल प्रदेश	8	1.09
31	सिक्किम	6	0.75
32	मिजोरम	6	0.92
	कुल	**54**	**41.13**
	सकल योग	**1244**	**1383.26**